CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य

वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

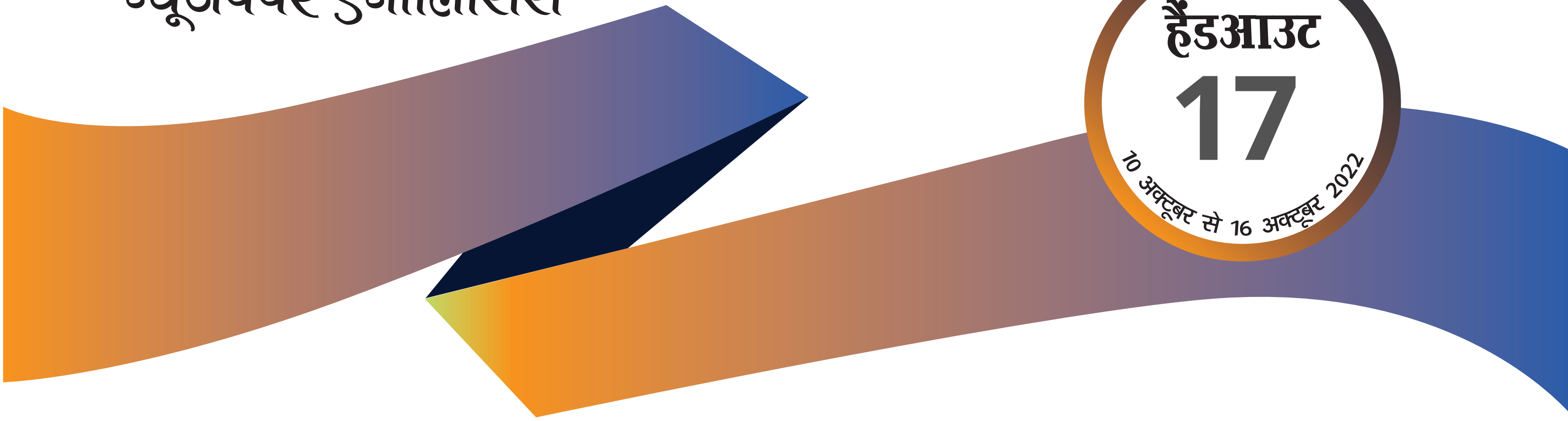

हैंडआउट
17
10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन ड्डार्थ आदि।

चाणक्य वीकली करेंट अफफेयर्स एडं न्यूजपेपर एनालिसिस
Web: www.chanakyaiasacademy.com, Email: enquiry@chanakyaiasacademy.com
Toll Free No. 1800 - 274 - 5005

वैश्विक भुखमरी सूचकांक

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स: आर्थिक और सामाजिक विकास - सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, आदि।**
- **मेन्स जीएस पेपर 2: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।**

महत्व:

- **प्रारंभिक परीक्षा: ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित तथ्य और निष्कर्ष**
- **मुख्य परीक्षा: उत्तर में इस्तेमाल किया जा सकता है**

संदर्भ :

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2022 में भारत 107 वें स्थान पर है। भारत 121 देशों में से अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) के बारे में:

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में लॉन्च किया गया था, GHI को शुरू में अमेरिका-आधारित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) और जर्मनी स्थित वेल्ट हंगरहिल्फे द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- 2007 में, आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्डवाइड भी एक सह-प्रकाशक बन गया।
- 2018 में, IFPRI ने इस परियोजना में अपनी भागीदारी को समाप्त किया और GHI,वेल्ट हंगरहिल्फे और कंसर्न वर्ल्डवाइड की संयुक्त परियोजना बन गई।

GHI क्या दर्शाता है?

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक निगरानी का एक साधन है कि देश भूख से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। इसे अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- SDG के लक्ष्य 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है।
- यह वर्ष के सभी समय में सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की सार्वभौमिक पहुंच के लिए भी प्रतिबद्ध है।

GHI को कैसे परिभाषित किया जाता है?

GHI स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है - शून्य सबसे अच्छा स्कोर है (अर्थात भूखमरी नहीं है) और 100 सबसे खराब है।

GHIभुखमरी के तीन आयामों को दर्शाता है–

1. अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति।
2. बाल मृत्यु दर।
3. पोषण के तहत बच्चा
    (a) बाल बौनापन
    (b) बाल निर्बलता

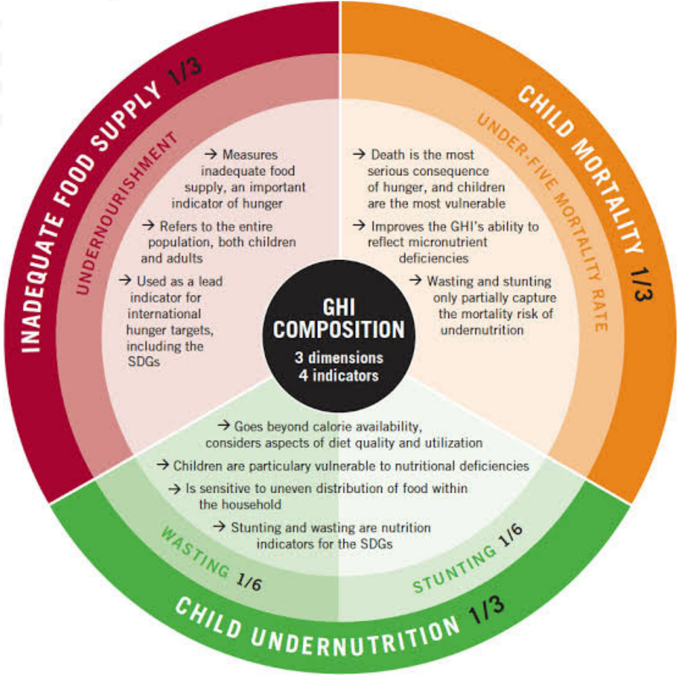
INADEQUATE FOOD SUPPLY 1/3
UNDERNOURISHMENT
→ Measures inadequate food supply, an important indicator of hunger
→ Refers to the entire population, both children and adults
→ Used as a lead indicator for international hunger targets, including the SDGs
CHILD MORTALITY 1/3
UNDER-FIVE MORTALITY RATE
→ Death is the most serious consequence of hunger, and children are the most vulnerable
→ Improves the GHI's ability to reflect micronutrient deficiencies
→ Wasting and stunting only partially capture the mortality risk of undernutrition
GHI COMPOSITION
3 dimensions
4 indicators
→ Goes beyond calorie availability, considers aspects of diet quality and utilization
→ Children are particulary vulnerable to nutritional deficiencies
→ Is sensitive to uneven distribution of food within the household
→ Stunting and wasting are nutrition indicators for the SDGs
WASTING 1/6
STUNTING 1/6
CHILD UNDERNUTRITION 1/3

परिणाम और निहितार्थ:

- भुखमरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसलिए इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।
- भुखमरी और अल्पपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो अक्सर पीढ़ी से पीढ़ी तक "चलता" रहता है।
- गरीब माता-पिता के बच्चे अक्सर कम वजन के पैदा होते हैं और बीमारी के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं; वे ऐसी परिस्थितियों में बड़े होते हैं जो उनके पूरे जीवन के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता को क्षीण कर देती हैं।
- एक उच्च वैश्विक भुखमरी सूचकांक में योगदान करने वाले कारकों की पहचान इस प्रकार की गई है–
    - कम आमदनी और गरीबी,
    - युद्ध और हिंसक टकराव,
    - सामान्य स्वतंत्रता का अभाव,
    - महिलाओं की निम्न स्थिति, और
    - खराब लक्षित और वितरित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम।

भारत का प्रदर्शन :

कुल मिलाकर, भारत ने अपना GHI स्कोर 2014 में 28.2 से 2022 में 29.1 होने के साथ थोड़ा खराब प्रदर्शित किया है।

चाइल्ड वेस्टिंग रेट-

- भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर (लम्बाई के अनुपात में कम वजन)19.3% है जो वर्ष 2014 (15.1%) और यहां तक कि वर्ष 2000 (17.15%) में दर्ज स्तरों से भी बदतर है।
- यह दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है और भारत की बड़ी आबादी के कारण इस क्षेत्र की औसत को बढ़ाती है।

अल्पपोषण -

- अल्पपोषण की व्यापकता, जो कि आहार ऊर्जा की कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात का एक उपाय है, देश में 2018-2020 में 14.6% से बढ़कर 2019-2021 में 16.3% हो गया है।
- भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 224 मिलियन है।

चाइल्ड स्टंटिंग(बौनापन) और मृत्यु दर -

- 2014 से 2022 के बीच बाल बौनापन 38.7% से घटकर 35.5% हो गया है।
- इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर भी 4.6 प्रतिशत से गिरकर 3.3 प्रतिशत हो गई है।

कॉलेजियम के कामकाज में समस्याएं

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स:** भारतीय राजनीति और शासन-संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे, आदि।
- **मेन्स जीएस पेपर 2:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

महत्व:

- **प्रारंभिक परीक्षा:** न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद और शक्तियां
- **मुख्य परीक्षा:** कॉलेजियम प्रणाली और उससे जुड़ी चुनौतियाँ

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक बैठक, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे, 30 सितंबर, 2022 को बुलाया गया। किंतु बैठक बिना आगे कोई विचार-विमर्श किये समाप्त कर दी गयी।

कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति

- संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। दोनों प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति के पास «उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्तियां करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे»।
- प्रथम न्यायाधीश के मामले में - एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई की «सहमति» की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले ने नियुक्तियों में कार्यपालिका की श्रेष्ठता की पुष्टि की, लेकिन 12 साल बाद दूसरे न्यायाधीशों के मामले में इसे उलट दिया गया।
- दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। इसने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों पर शीर्ष अदालत में अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना होगा।
- 1998 में तीसरा न्यायाधीश मामला(थर्ड जजेज केस) , जो कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, ने कॉलेजियम को भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके चार सबसे वरिष्ठ जजों की वर्तमान संरचना तक विस्तारित किया।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना

- **असंवैधानिक और निरंकुश:** ‹कॉलेजियम› का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और इसे न्यायपालिका द्वारा स्वयं न्यायाधीशों का चयन करने की शक्ति बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।
- **अलोकतांत्रिक:** कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों का चयन अलोकतांत्रिक है क्योंकि न्यायाधीश लोगों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा नहीं चुने जाते हैं और लोगों या किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
    - 2014 में लाया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को एक प्रमुख भूमिका प्रदान करता, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
- **भाई-भतीजावाद को बढ़ावा:** पिछले न्यायाधीशों या वरिष्ठ वकीलों के बेटे और भतीजे न्यायिक भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय विकल्प होते हैं। इस प्रकार, यह प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर न्यायपालिका में औसत दर्जे को प्रोत्साहित करता है।
- **अक्षम:** कॉलेजियम न्यायाधीशों की रिक्तियों और अदालतों में मामलों के बढ़ते मामलों को रोकने में सक्षम नहीं है।
- **पारदर्शिता की कमी:** अपारदर्शी होने के लिए कॉलेजियम के कामकाज की आलोचना की गई है। इसके प्रस्तावों और सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें इसके फैसलों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाती है। हालांकि, विचार-विमर्श की प्रकृति और क्या किसी विशेष उम्मीदवार की उपयुक्तता पर कोई आंतरिक मतभेद हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नही दी जाती हैं।
- **निर्णय लेने की गति को धीमा करना:** भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता द्वारा की जाती है, उनमें से कई का कार्यकाल कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया निर्णय लेने को धीमा कर सकती है।

पीएम-डिवाइन

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स:** भारतीय राजनीति और शासन - संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे, आदि।
- **मेन्स जीएस पेपर 2:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

महत्व:

- **प्रारंभिक परीक्षा:** पीएम-डिवाइन योजना, एमडीओएनईआर, अन्य परियोजनाओं से संबंधित तथ्य।
- **मुख्य परीक्षा:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) को मंजूरी दे दी है - पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नई योजना जिसे इस साल की शुरुआत में केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था।

पीएम-डिवाइन: तथ्य

- **योजना की प्रकृति:** पीएम-डिवाइन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100% केंद्रीय वित्त पोषण है।
- **संबद्ध मंत्रालय और एजेंसी**: इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** पीएम-डिवाइन योजना चार साल की अवधि 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष) के लिए है।
- पीएम-डिवाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा और युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा।
- पीएम-डिवाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के पर्याप्त संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि वे टिकाऊ हों।

उद्देश्य:

- पीएम गति शक्ति में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढाँचे को निधि देना;
- एनईआर द्वारा महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;
- युवाओं और महिलाओं के लिये आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को कम करना।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विकास की क्या आवश्यकता है?

- इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति, भारत को मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से जोड़ती है, साथ ही यह एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए इसे महत्वपूर्ण हो जाती है।
    - भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक कूटनीतिक पहल है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की भू-रणनीतिक स्थिति महत्वूर्ण है, यह बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और नेपाल के साथ सीमाओं को साझा करता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्पूर्ण हो जाता है और इसे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी महत्वपूर्ण बनाता है।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता में समृद्ध है। हालांकि, उत्तर पूर्व क्षेत्र को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके विकास में बाधा डालती हैं जिसमें सशस्त्र विद्रोह, सीमा पार प्रवास और जातीय संघर्ष आदि शामिल हैं।
- बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में पूर्वोत्तर राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और नीति आयोग, यूएनडीपी और एमडीओएनईआर द्वारा तैयार उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार यहाँ महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं कमियों और विकास अंतराल को दूर करने के लिए नई योजना, पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

एमडीओएनईआर

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MD0NER) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन और निगरानी से संबंधित मामलों के लिए गठित संस्था है। इसका कार्य क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करना है ताकि यह देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की समानता को हासिल कर सके।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए अन्य परियोजनाएं

- **उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी)**
  - **सहायता प्रदान** : एशियाई विकास बैंक (ADB)
  - **परियोजना का उद्देश्य:** इस योजना में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के 6 पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 433.425 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण/उन्नयन की परिकल्पना की गई है।
- **उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना**
  - **सहायता प्रदान:** विश्व बैंक द्वारा
  - **परियोजना का उद्देश्य:** चार पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और सबसे अधिक वंचितों की ग्रामीण आजीविका में सुधार करना।
  - इस परियोजना के चार प्रमुख घटक हैं:
    - सामाजिक सशक्तिकरण;
    - आर्थिक सशक्तिकरण;
    - साझेदारी विकास और प्रबंधन और
    - परियोजना प्रबंधन।

हरित पटाखे

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स:** सामान्य विज्ञान।
- **मेन्स जीएस पेपर 3:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

महत्व:

- **प्रारंभिक परीक्षा:** ग्रीन क्रैकर्स
- **मुख्य परीक्षा:** हरे पटाखे और वे प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वह वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करना चाहती है। इस बीच, कुछ राज्यों ने दिवाली पर 'ग्रीन पटाखों' के इस्तेमाल की अनुमति दी है।

हरित पटाखे क्या हैं?

ग्रीन पटाखे कम उत्सर्जन वाले पटाखे होते हैं जो सल्फर नाइट्रेट्स, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और बेरियम जैसे हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। उन्हें पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने के लिए डिज़ाइन किया गया था - इस प्रक्रिया में, स्वास्थ्य जोखिम और मनुष्यों के लिए खतरों को कम करना शामिल है।

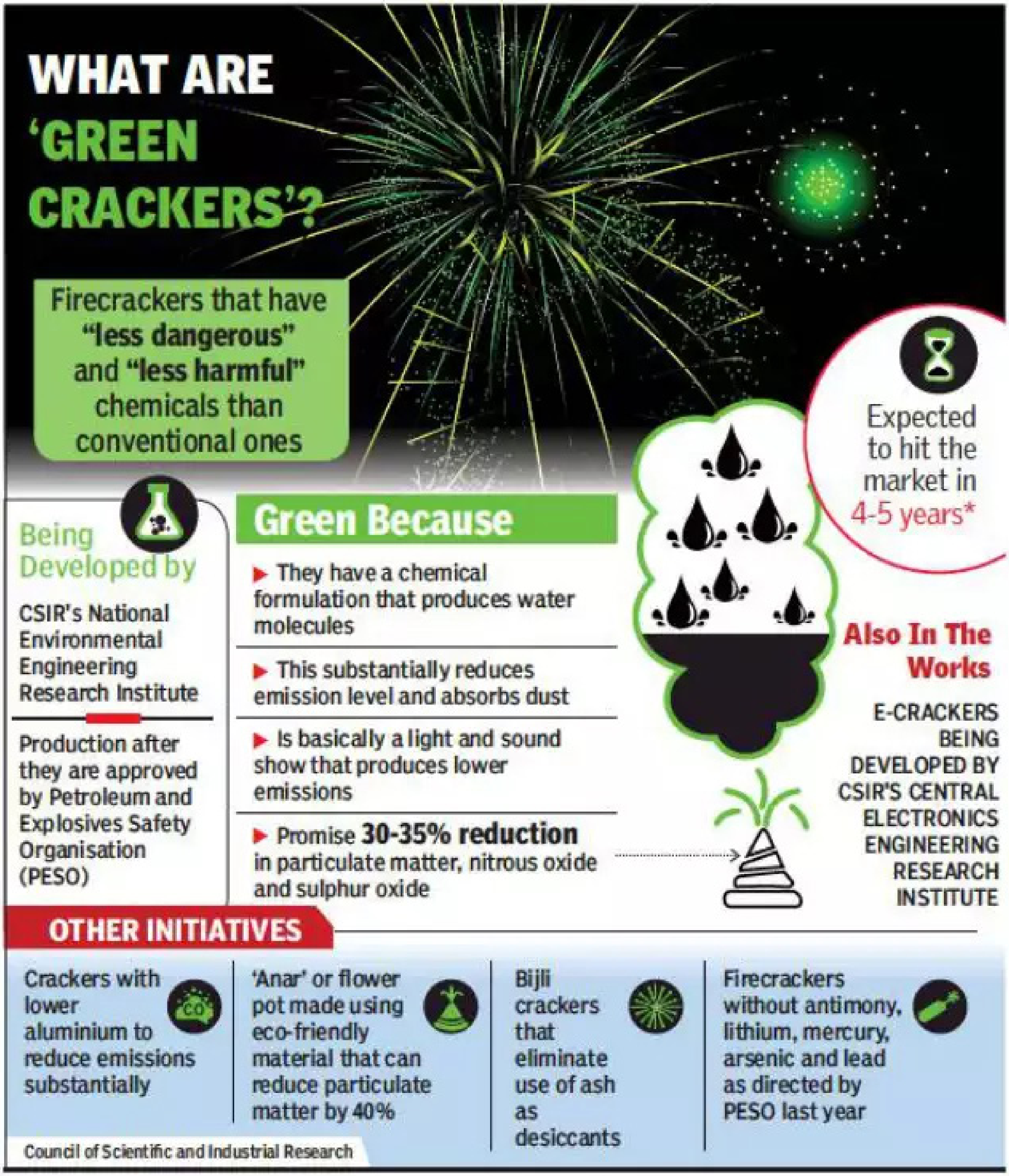

WHAT ARE 'GREEN CRACKERS'?

Firecrackers that have "less dangerous" and "less harmful" chemicals than conventional ones

Being Developed by

CSIR's National Environmental Engineering Research Institute

Production after they are approved by Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO)

Green Because

- They have a chemical formulation that produces water molecules
- This substantially reduces emission level and absorbs dust
- Is basically a light and sound show that produces lower emissions
- Promise **30-35% reduction** in particulate matter, nitrous oxide and sulphur oxide

Expected to hit the market in 4-5 years*

Also In The Works

E-CRACKERS BEING DEVELOPED BY CSIR'S CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE

OTHER INITIATIVES

- Crackers with lower aluminium to reduce emissions substantially
- 'Anar' or flower pot made using eco-friendly material that can reduce particulate matter by 40%
- Bijli crackers that eliminate use of ash as desiccants
- Firecrackers without antimony, lithium, mercury, arsenic and lead as directed by PESO last year

Council of Scientific and Industrial Research

हरित और पारंपरिक पटाखों में अंतर

पारंपरिक पटाखों के विपरीत, हरे पटाखों में एल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट या कार्बन जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, हरित पटाखे नियमित पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा, ये पटाखे कम शोर भी करते हैं, जो 160 डेसिबल से 110 डेसिबल तक की गिरावट दिखाते हैं।

क्या वे 100% पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं?

नहीं, वे नहीं हैं। वे भी प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं लेकिन यह पारंपरिक प्रदूषकों की तुलना में 30% कम है।

ग्रीन क्रैकर्स: SWAS, SAFAL और STAR

- **SWAS - सुरक्षित जल रिलीजर**
    - **वे हवा में जलवाष्प छोड़ेंगे जो निकलने वाली धूल को दबा देगी**
    - **इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल नहीं होंगे**
    - **गैसीय उत्सर्जन के लिए एक मंदक छोड़ा जाएगा**
    - **निकलने वाली पार्टिकुलेट डस्ट लगभग 30 प्रतिशत कम हो जाएगी**
- **STAR - सुरक्षित थर्माइट पटाखा**
    - पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल नहीं है
    - कम पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल
    - कम ध्वनि तीव्रता
- **SAFAL - सेफ मिनिमल एल्युमीनियम**
    - एल्यूमीनियम का न्यूनतम उपयोग
    - एल्यूमीनियम के बजाय मैग्नीशियम का उपयोग
    - पारंपरिक पटाखों की तुलना में ध्वनि में कमी

मानव पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

- वातावरण में मौजूद कणों से मानव स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होता है। कण नाक में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं। यह बहती नाक का कारण भी बन सकता है।
- PM 2.5 फेफड़ों में प्रवेश कर सकता है और रक्त प्रणाली में भी प्रवेश कर सकता है। वे हृदय और सांस की बीमारियों के साथ-साथ फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं।
- वायु प्रदूषण फेफड़ों की क्षति और सीमित फेफड़ों के कार्य से भी जुड़ा हुआ है।
- वायु प्रदूषण का हृदय पर भी गम्भीर प्रभाव हो सकता है - यह रक्तचाप को बढ़ा सकता है और हृदय की पहले से मौजूद समस्याओं को बढ़ा सकता है।
- प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मौत का खतरा काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, हृदय रोगों के प्रति संवेदनशील लोगों को अधिक जोखिम होता है।
- वायु प्रदूषण भारत में औसत जीवन प्रत्याशा को कम करता है।
    - शिकागो विश्वविद्यालय (ईपीआईसी) में ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण से भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में 6-7 साल की कमी होगी।
    - दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली के मामले में, लोगों को अपने जीवन के 10 साल गंवाने होंगे।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स: पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे - जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है।**
- **मेन्स जीएस पेपर 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।**

महत्व:

- **प्रारंभिक परीक्षा: रिपोर्ट के तथ्य और निष्कर्ष**
- **मुख्य परीक्षा: उत्तर में इस्तेमाल किया जा सकता है**

संदर्भ :

- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी में 69 प्रतिशत की गिरावट आई है।

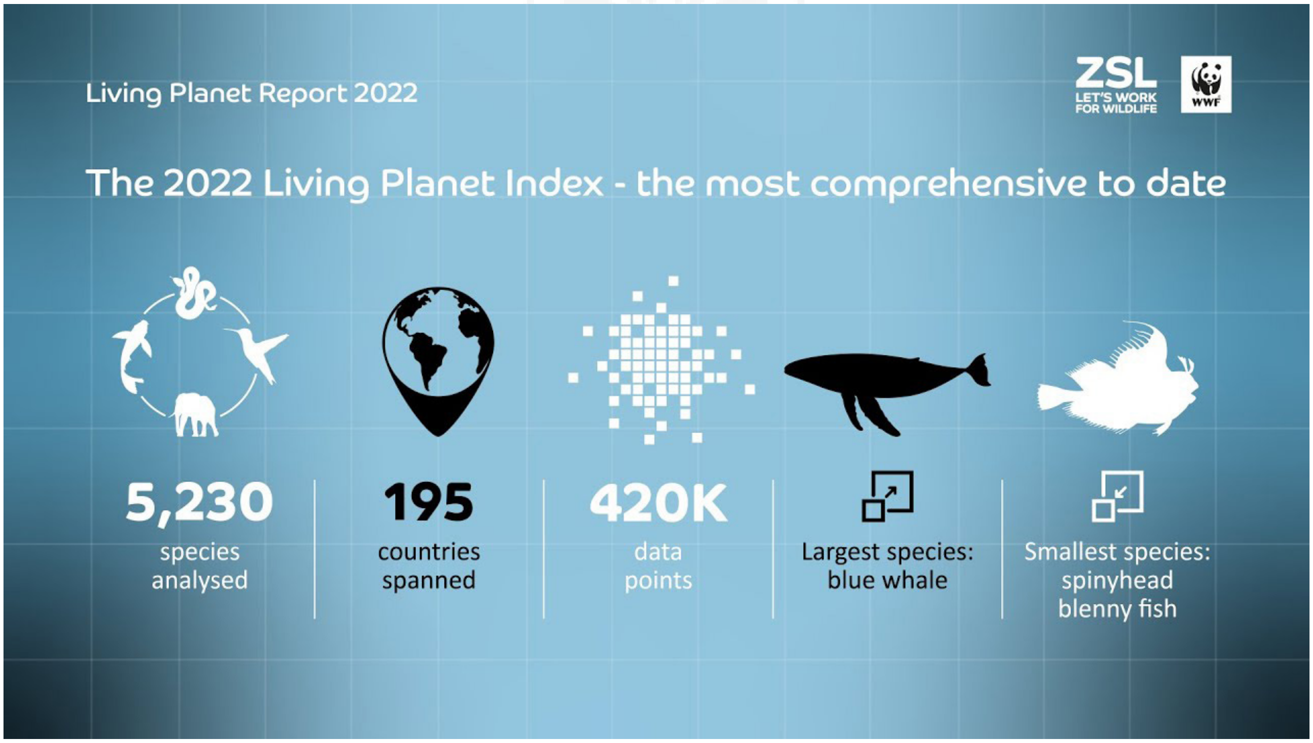

Living Planet Report 2022

The 2022 Living Planet Index - the most comprehensive to date

5,230 species analysed

195 countries spanned

420K data points

Largest species: blue whale

Smallest species: spinyhead blenny fish

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) के बारे में:

- यह 1961 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है।
- यह व्यक्तियों और वसीयत (वसीयत द्वारा दी गई संपत्ति), सरकारी स्रोतों (जैसे विश्व बैंक, USAID, आदि) से 17% और 2020 में निगमों से 8% से 65% धन के वित्तपोषण के साथ एक संस्थान है।
- 1995 के बाद से, WWF ने ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ 12,000 से अधिक संरक्षण पहलों में $ 1 बिलियन से अधिक का निवेश किया है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं।

WWF के छह महत्वाकांक्षी लक्ष्य:

CLIMATE

Create a climate-resilient and zero-carbon world, powered by renewable energy.

FOOD

Double net food availability; freeze its footprint.

FORESTS

Conserve the world's most important forests.

FRESHWATER

Secure water for people and nature.

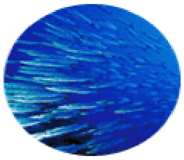

OCEANS

Safeguard healthy oceans and marine livelihoods.

WILDLIFE

Protect the world's most important species.

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट:

- WWF द्वारा 1998 से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और मानव गतिविधि के प्रभाव पर दुनिया का अग्रणी, विज्ञान आधारित विश्लेषण है।
- यह लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और पारिस्थितिक पदचिह्न गणना पर आधारित है।
- WWF के सहयोग से जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) द्वारा प्रबंधित लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, विश्व भर से प्रजातियों की कशेरुकी आबादी में रुझानों के आधार पर वैश्विक जैव विविधता की स्थिति का एक संकेतक है।

रिपोर्ट 2022:

- WWF के इस प्रमुख प्रकाशन के अनुसार, 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है।
- WWF के अनुसार, ताजे पानी की आबादी में 1970 और 2018 के बीच औसतन 83% की गिरावट आई है।
- 1970 और 2018 के बीच, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों ने दुनिया भर में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी में सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव किया, जिसमें औसतन 94% की गिरावट आई।
- बढ़ते तापमान पहले से ही बड़े पैमाने पर विलुप्त होने और पूरी प्रजाति के पहले विलुप्त होने का कारण बन रहे हैं (ब्रम्बल केई मेलोमिस - एक छोटा ऑस्ट्रेलियाई कृंतक, समुद्र के स्तर में वृद्धि के बाद विलुप्त घोषित किया गया था)।
- गर्म पानी की प्रवाल भित्तियां(मूंगे की चट्टान) पहले ही अपनी आबादी का 50% खो चुकी हैं, और 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के परिणामस्वरूप 70 - 90% का नुकसान अनुमानित है।
- उनके महत्त्व के बावजूद, जलीय कृषि, कृषि और तटीय विकास द्वारा प्रति वर्ष 0.13% की दर से मैंग्रोवों की कटाई की जा रही है।
- मैंग्रोव नुकसान तटीय समुदायों के लिए आवास के नुकसान के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- उदाहरण के लिए, सुंदरवन मैंग्रोव वनों के कटाव के कारण वहां रहने वाले लगभग 10 मिलियन लोगों के लिए भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में गिरावट आई है।

- यह मुख्य रूप से समुद्र और भूमि के उपयोग में बदलाव, जीवों के प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण है।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि कृषि, उभयचरों (जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले जानवर) के लिए सर्वाधिक खतरा है, जबकि शिकार से पक्षियों और स्तनधारियों के लिए सबसे अधिक खतरा है।

भारत के विशिष्ट निष्कर्ष:

- WWF इंडिया के कार्यक्रम निदेशक के अनुसार, इस अवधि के दौरान देश में मधुमक्खियों और मीठे पानी के कछुओं की 17 प्रजातियों की आबादी में गिरावट आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट देश में जैव विविधता के नुकसान के मामले में संवेदनशील क्षेत्रों में से कुछ हैं, और यदि तापमान में वृद्धि होती है तो भविष्य में जैव विविधता के नुकसान में वृद्धि होने की आशंका है।
- हाल ही में चीता स्थानान्तरण जैसी परियोजनाएं प्रजातियों के संरक्षण के लिए फायदेमंद हैं और भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर या एक सींग वाले गैंडों और शेरों के लिए परियोजनाओं जैसी सफलताएं हासिल की हैं।
- इन प्रजातियों के संरक्षण के कारण, उस निवास स्थान में रहने वाली अन्य सभी प्रजातियों पर एक छत्र प्रभाव पड़ता है।

सुझाव :

- जब संरक्षण के प्रयास लाभप्रद होते हैं, प्रकृति के नुकसान को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई (साहसिक और अधिक महत्वाकांक्षी संरक्षण प्रयासों सहित) की आवश्यकता होती है।
- हम जिस तरह से उत्पादन और उपभोग करते हैं, उसमें परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता होती है, जैसे कि खाद्य उत्पादन और व्यापार की दक्षता में वृद्धि, कचरे को कम करना और स्वस्थ और अधिक टिकाऊ आहार का समर्थन करना।
- व्यक्तिगत छोटे कार्य भले ही पर्याप्त न हों लेकिन सामूहिक रूप से दुनिया भर के लोगों में परिवर्तन करने की शक्ति है।

अभ्यास प्रश्न

1. **भारत में उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

   1. संविधान में कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
   2. कॉलेजियम के सदस्यों का पांच साल का निश्चित कार्यकाल होता है।
   3. न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की सलाह बहुत सीमित है और वह कॉलेजियम की सलाह को वापस नहीं भेज सकती है।

   उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. **हरित पटाखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

   1. वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि वे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं।
   2. यह एक रासायनिक सूत्र पर कार्य करता है जो जल-कणों का उत्पादन करता है।

   उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. **पीएम डिवाइन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

   1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
   2. इसे गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
   3. यह योजना 15वें वित्त आयोग के साथ समाप्त होगा ।

   उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 3

   (c) केवल 3 (d) केवल 1 और 2

4. **वैश्विक भूख सूचकांक के संबंध में गलत कथन का चयन करें**

   (a) एसडीजी के लक्ष्य 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है।

   (b) भारत वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई), 2022 में 107 वें स्थान पर है।

   (c) ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2006 में बनाया गया ।

   (d) वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई)में भूख के चार आयामों में रखा गया है।

5. **लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार-**

   1. 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई है।
   2. गर्म पानी के कोरल पहले ही अपनी 50% आबादी खो चुके हैं।

   उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर

1	2	3	4	5
D	B	C	D	C

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।